| Publication : Mahanagar Times | Subject : AVI requests Rajasthan Govt to Regulate Vaping |
|---|---|
| Date of Publish : 08th June 2018 | Edition : Jaipur |

महानगर टाइम्स

# ई-सिगरेट को विनियमित करने की एवीआई ने की सरकार से मांग

**वाणिज्य संवाददाता**

जयपुर। ई-सिगरेट यूजर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन एसोसिएशन ऑफ वैपर्स इंडिया (एवीआई) ने राजस्थान में ई-सिगरेट और वैपिंग को विनियमित करने के लिए नीति तैयार करने में राज्य सरकार को मदद करने की पेशकश की है।

इसमें कहा गया कि प्रतिबंध से जहां लोग सुरक्षित विकल्पों से वंचित हो जाएंगे, वहीं तम्बाकू उद्योग को संरक्षण मिल सकेगा। मौजूदा वक्त में धूम्रपान में कमी की महज 5.6 फीसदी की दर से कई लोगों की जान नहीं बच सकती है। एवीआई के डायरेक्टर सम्राट चौधरी ने कहा कि यह इस बात का संकेत है कि सरकार को अब अतिरिक्त प्रयास करने चाहिए। धूम्रपान की तुलना में ई-सिगरेट एक कम नुकसानदायक विकल्प है। ऐसा अमेरिका, यूके और यूरोपियन यूनियन जैसे विकसित देशों में देखने को मिला है। एवीआई पदाधिकारियों ने सुझाव दिया कि कोई नीति बनाते समय राजस्थान सरकार को इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि ई-सिगरेट को अपनाने से धूम्रपान करने वालों को होने वाला संभावित नुकसान 95 प्रतिशत तक कम हो सकता है। एवीआई के को-डायरेक्टर प्रतीक गुप्ता ने कहा, 'हम सरकार को ऐसे पुराने धूम्रपान करने वालों से भी रूबरू कराएंगे, जिन्होंने ई-सिगरेट के इस्तेमाल से धूम्रपान छोड़ दिया और उनके जीवन में खासा सुधार देखने को मिला।' हम ई-सिगरेट को विनियमित करने और अवयस्कों व नॉनयजर्स को इसकी बिक्री पर रोक लगाने के सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं। धूम्रपान को बढ़ावा देने और कम जोखिम वाले विकल्पों की ओर रुख किए जाने के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है।